सांध्य दैनिक 4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 10 ● अंक: 158 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार, 13 जुलाई, 2024

मूल्य ₹ 3/-

हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा सम्बन्ध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हों।

-ब्रह्माकुमारी शिवानी

हार जीत होती रहती है, न करें भद्दी... 2 | आतंकी हमले के बाद सियासी... 3 | अगर हम ऐसी ही गलती करते... 7

उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने जमाई धाक, एनडीए गठबंधन की गिरी साख

लोगों ने बीजेपी व मोदी को नकारा

- हिमाचल में दो सीटें कांग्रेस ने जीतीं, एक भाजपा के खाते में
- मप्र के अमरवाड़ा मुकाबले में भाजपा की जीत, अंतिम राउंड में कमलेश शाह ने मारी बाजी
- पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी की जीत
- बिहार के रूपौली से निर्दलीय शंकर सिंह जीते बीमा हार गईं
- पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 में करारा झटका खाने के बाद भाजपा को उपचुनावों में करारी चोट लगी है। उसे पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल तक अपनी सीटें गंवानी पड़ी है। 13 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाकर एकबार फिर अपनी धाक जमाई है। उधर बीजेपी की हार से एनडीए की साख को बट्टा भी लग गया है। इन सबके बीच भाजपा के नेताओं के बीच से अपनी ही पार्टी व शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावती सुर भी उठने लगे हैं।

अब तो बड़े से बड़ा नेता व छोटे से छोटा कार्यकर्ता के मुंह से मोदी नहीं चाहिए का आवाज आने लगी है। वहीं उपचुनाव में जिस तरह इंडिया के सहयोगी दलों को जनता का समर्थन मिल रहा है उससे तो ऐसा लगता है लोगों का अब भाजपा से मोहभंग भी हो रहा है। बीजेपी के पिछड़ने पर कांग्रेस ने भी तंज कसते हुए कहा है कि धीरे-धीरे मोदी युग का अंत हो रहा है। बता दें सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है। जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु शामिल हैं।

13

में से 11 सीटों पर गठबंधन आगे

उत्तराखंड की मंगलौर सीट भाजपा के हाथ से निकली, काजी की जीत, बदरीनाथ में भी कांग्रेस जीती

पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने दिया बीजेपी को झटका

पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चारों सीटें जीत ली है। राणाघाट दक्षिण से टीएमसी उम्मीदवार मुकुट मणि अधिकारी ने उपचुनाव की मतगणना पर कहा, 5 राउंड की गिनती के बाद हमारी पार्टी यहां आगे चल रही है, लोगों ने हमें जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है, उसके आधार पर हमें लगता है कि समर्थन और बढ़ेगा और हमारी पार्टी की जीत होगी।

जनता ने खरीद-फरोख्त का दिया जवाब : सुक्खू

खरीद-फरोख्त हिमाचल में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है... देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख दांव पर लगाई थी, 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां जीत नहीं पा रही थी। जब मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मैदान में उतारता है तो उसकी साख भी दांव पर होती है, भाजपा ने पूरा जोर लगाया लेकिन मैं देहरा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और कमलेश ठाकुर की एक अच्छी जीत हो रही है। मैं उन्हें बधाई देता हूं।

देहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हिमाचल की जनता ने हमें 2022 में 40 सीटें दी थी, हमें फिर से जिताना जनता ने तय किया है। जिस प्रकार की

जालंधर पश्चिम सीट पर जीती आप

जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने जीत हासिल की है। यहां दूसरे स्थान पर कांग्रेस और तीसरे स्थान पर भाजपा उम्मीदवार रहे। पंजाब सरकार में मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया।

2027 में यूपी में सरकार बनना मुश्किल : बीजेपी विधायक

- इंडिया गठबंधन का पीडीए लगातार बढ़त ले रहा है

लखनऊ। जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा के एक बयान ने उत्तर प्रदेश के सियासत में बवाल मचा रखा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आज जो हमारी सरकार की स्थिति है वह बहुत खराब और कमजोर है। अगर हमारी ऐसी ही हालत रही तो 2027 के चुनाव आने तक हमारी स्थिति और कमजोर हो सकती है जिससे हमारी सरकार बनने के संभावनाएं भी खत्म हो जाएगी।

वर्तमान में जो स्थिति है, उससे तो यही लगता है कि हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है। इसकी वजह से लोगों में व्यापक तौर पर भ्रम की स्थिति है। लोग समाजवादी पार्टी की बातों में आ रहे हैं और भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। भाजपा विधायक ने केंद्रीय नेतृत्व से भी हस्तक्षेप की मांग की। आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति है, उसमें पीडीए आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

एलजी की शक्ति बढ़ाने के आदेश पर सियासी भूचाल

- दिल्ली की तरह ट्रांसफर-पोस्टिंग में उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी
- विपक्ष ने उठाए सवाल बोला राज्य के हितों का हनन
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होने हैं सितंबर में विस चुनाव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों को नजदीक देखकर केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जम्मू-कश्मीर सितंबर तक विस के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। इस फैसले बाद सियासी भूचाल भी आ गया है। विपक्ष ने इस पर एनडीए की मोदी सरकार पर करारा वार किया है।

नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी व कांग्रेस ने इस फैसले का राज्य के अधिकारों का हनन बताया है। जम्मू-कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर केंद्र का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास होंगी। 42ए- कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत 'पुलिस', 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'अखिल भारतीय सेवा' और 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (एसीबी) के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। 42बी- अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

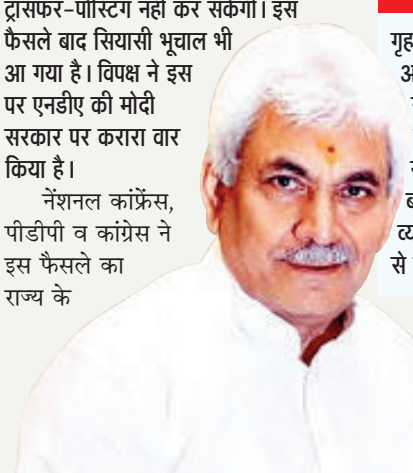

पुलिस, कानून व्यवस्था पर होगी उपराज्यपाल की पकड़

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा शक्ति देने वाली नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इस संशोधन के बाद उपराज्यपाल को अब पुलिस, कानून व्यवस्था, ऑल इंडिया सर्विस (एआईएस) से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे।

हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी : उमर

केंद्र के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा- एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टाम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।

हार जीत होती रहती है, न करें भद्दी बातें : राहुल गांधी

पूर्व सांसद स्मृति ईरानी पर हो रही टिप्पणियों से नेता प्रतिपक्ष नाराज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोगों से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अन्य नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- हार-जीत जीवन में लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक या भद्दी टिप्पणी न की जाए।

किसी का अपमान करना या किसी को नीचा दिखाना यह शक्तिशाली होने का नहीं कमजोर होने का प्रदर्शन करना है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।

उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपना आधिकारिक बंगला खाली करने पर ईरानी पर कटाक्ष कर रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी शर्मा से अमेठी संसदीय सीट पर 1.6 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हारने के कुछ हफ्ते बाद ईरानी ने लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया।

अमेठी के विकास के लिए है सांसद निधि : शर्मा

सांसद निधि अमेठी और यहां की जनता के लिए है। सार्वजनिक कार्य के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा तो उसका सहयोग किया जाएगा। ये बातें सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहीं। वह ब्लॉक भेटुआ परिसर में क्षेत्र पंचायत की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास खंड विकास की सबसे छोटी इकाई है। यही से विकास शुरू होता है। उन्होंने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व जिला पंचायत सदस्यों से बात की। बैठक में जिस भी एजेंडे पर चर्चा हुई है वे विकास कार्य समय से पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करने की बात कही।

गांव के विकास पर हो चर्चा: सिंह

बैठक में मौजूद एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गांव के विकास के लिए जो भी संभव होगा, वे पूरा प्रयास करेंगे। बैठक में ब्लॉक की 47 ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी गई। इसके साथ ही प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख आकर्ष शुक्ल ने की। बैठक में खंड विकास अधिकारी विजय अस्थाना, डीडीसी सूबेदार यादव, रमेश सिंह, शीतला प्रसाद तिवारी, जगन्नाथ तिवारी समेत ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे।

बाढ़ और जलभराव रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही सरकार: अखिलेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» सपा अध्यक्ष बोले- भाजपा लोगों से भेदभाव करती है और वादे पूरे नहीं करती

लखनऊ। यूपी में बाढ़ से हो रही घटनाओं पर योगी सरकार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से गोरखपुर समेत दर्जनों जिलों में जलभराव है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ से जनजीवन त्रस्त है। समय रहते बाढ़ और जलभराव रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। इसी रणनीति के तहत वह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने भाजपा से सावधान रहने की सलाह दी। आरोप लगाया कि वोट न देने वालों से बदला लेने की तैयारी है। वह लोगों से भेदभाव करती है और वादे पूरे नहीं किए।

विप चुनाव में खुला उद्धव गुट का खाता

मिलिंद नार्वेकर को मिली जीत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के मिलिंद नार्वेकर विधानपरिषद के चुनाव में जीत गए हैं और शेकाप के जयंत पाटिल हार गए हैं। महाविकास अघाड़ी के 64 वोटों पर गौर करें तो पांच वोट बंटे हैं। माविया के साथ रहे दो विधायकों शंकरराव गडाख और विनोद निकोले के वोट गिने जाएंगे।

मावि के कुल 7 वोट बंटने की बात सामने आयी है। शेकाप के जयंत पाटिल ने कहा कि मुझे मेरे 12 वोट मिले हैं और कांग्रेस के कुछ वोट बंट गए हैं।

बीजेपी के पांच, शिंदे-पवार की पार्टी से दो प्रत्याशी जीते

महाराष्ट्र विधानपरिषद में महायुति के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं। पांच बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। शिंदे की शिवसेना के खाते में 2 और अजित पवार की एनसीपी के 2 उम्मीदवार मिली हैं। एक उम्मीदवार कांग्रेस के विजयी हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे, परिणय फुके और योगेश टिलेकर ने जीत हासिल की है। पंकजा मुंडे को 26, परिणय फुके को 26, योगेश टिलेकर को 26 वोट मिले हैं। विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन में घटक दल अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। शिवाजीराव गर्जे और राजेश विटेकर दोनों प्रथम वरीयता के वोटों से जीते। अजित पवार ने कहा कि हमारे पास 42 वोट थे, लेकिन हमें 47 वोट मिले।

एमवीए का अहंकार खत्म : मुनगंटीवार

महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महायुति के सभी 9 उम्मीदवार चुने गए। हम बहुत खुश हैं। एमवीए का अहंकार खत्म हो गया है। एमएलसी चुनाव पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि पांच विधायकों ने हमें समर्थन दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जब चुनाव होते हैं तो आरोप लगते हैं लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोचता। महायुति को विधानसभा में भी ऐसी सफलता मिलनी चाहिए।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

पुल नहीं 18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं: तेजस्वी यादव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार की एनडीए सरकार घेरने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। उन्होंने एकबार फिर बिहार में गिरते पुलों व बढ़ते अपराध पर सीएम नीतीश कुमार व भाजपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने ने दावा किया है कि बिहार में 3 हफ़्तों में 17 पुल गिरे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे है।

बिहार में पुल ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक ढह रहे हैं - कुछ बिल्कुल नए और कुछ अभी भी निर्माण चरण में हैं। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, बिहार हमेशा से ही पुल टूटने के मामले में कुख्यात रहा है। अभी कुछ साल पहले ही भागलपुर में गंगा पर बना नया पुल टूट गया था। भारी मॉनसून के अलावा बिहार में पुल गिरने के और भी बहाने सामने

जदयू ने भी राजद पर किया पलटवार

आ रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने गहन जांच के निर्देश दिया है। फिलहाल इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में विश्वरिकॉर्ड बनाया है। विगत 3 हफ़्तों में अभी तक सिर्फ़ 17 ही पुल गिरे है। पुलियों के गिरने और धँसने की तो कोई गिनती ही नहीं।

राजद कार्यकाल के दौरान बनाए गए पुल ही टूटे : प्रेम कुमार

बिहार के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार में पुल ढहने की हालिया घटनाओं के लिए पूर्व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केवल राजद कार्यकाल के दौरान बनाए गए पुल ही टूट रहे हैं। कुमार ने कहा कि राजद कार्यकाल के दौरान बने पुल टूट रहे हैं। उन्होंने पुलों का निर्माण तो किया लेकिन रखरखाव की कोई नीति नहीं बनाई। हम जल्द ही एक रखरखाव नीति लाएंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जांच जारी है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं एक-एक चीज की जांच करा रहा हूं। मैंने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने किए रामलला के दर्शन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अयोध्या। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला व हनुमंतलला के दरबार में हाजिरी लगाई। वे शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरे।

वहां से व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के मध्य वे सरयू तट स्थित पर्यटन विभाग के होटल गए। जहां थोड़ी देर विश्राम के बाद वे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां करीब 20 मिनट तक पूजा-अर्चना के बाद राममंदिर के लिए रवाना हुए। रामलला के दरबार में उन्होंने करीब 15 मिनट तक पूजा-अर्चना की। उन्होंने राममंदिर की भव्यता

को भी निहारा। उन्हें मंदिर निर्माण के कार्यों के बारे में भी बताया गया। करीब ढ़ाई घंटे तक वे अयोध्या में रहे और शाम को वापस चले गए।

आतंकी हमले के बाद सियासी धमाका

उमर बोले- हम आतंकवादी हमलों से निपटने और जवाब देने में सक्षम

- नेकां व कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा
- फारूक ने पाकिस्तान को लगाई लताड़
- उमर ने कहा- सुरक्षा बलों पर भरोसा रखना चाहिए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आंतकी हमले व आपरेशन को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। राज्य के सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर एनडीए सरकार व बीजेपी आ गई है। नेकां नेता फारूख अब्दुल्ला, उमर, पीडीपी नेता महबूबा से लेकर कांग्रेस तक ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इन नेताओं ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया है। पर इन सबके बीच एनडीए सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। उधर इस हमले को लेकर सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बैठक कर जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा पर गंभीर चिंता की गई।

वहीं अन्य बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा पर देश के हर कोने से श्रद्धालु जाते हैं, ऐसे में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की रूपरेखा तैयार की गई। मीटिंग में मौजूदा अफसरों ने बताया कि आतंकी अब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर अपने गिरोह और हैंडलरों से बात करते हैं, ऐसे में बीएसएफ, एनआईए और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद लेने के लिए रणनीति तय की गई। उमर ने कहा, हमें अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा रखना चाहिए और अगर हम आतंकवादियों को सर्वोच्चता देना चाहते हैं तो चुनाव न कराएं। कश्मीर ने बदतर हालात का सामना किया है, लेकिन इससे जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रि या पर कभी असर नहीं पड़ा। पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 मामले पर अपने फैसले के दौरान, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सितंबर 2024 तक या उससे पहले जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद, प्रधान मंत्री और दोनों गृह मंत्री ने शीर्ष अदालत के आदेशानुसार इन चुनावों को समय पर कराने की पुष्टि करते हुए कई बयान जारी किये।

आतंकवाद को खत्म करने में विफल एनडीए सरकार : रसूल

जम्मू संभाग में बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को जम्मू शहर में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रसूल ने केंद्र सरकार पर आतंकवाद को रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाया। रसूल ने कहा, पिछले तीन सालों में

जम्मू संभाग में लगातार आतंकी हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसमें 42 के करीब जवानों ने अपना बलिदान दिया है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को यूटी बना कर आतंकवाद को खत्म करने के कई दावे किए। चुनाव को दौरान भी देशभर में इसका ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन वास्तविकता में मोदी सरकार आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में पांच सैनिक बलिदान हो गए और पांच घायल हुए। इससे पहले भी कठुआ, रियासी, डोडा, भद्रवाह जैसे इलाकों में आतंकी हमला कर चुके हैं। ये वे इलाके हैं जिनमें आतंकवाद का अबतक प्रभाव नहीं नजर आता था, लेकिन अब आए दिन इन जगहों पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के आतंकवाद को खत्म करने के सभी दावे खोखले नजर आते हैं।

उमर और फारूक भारत में पाकिस्तान के राजदूत हैं : चुघ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जम्मू-कश्मीर में उल्लेखनीय विकास और शांति को स्वीकार नहीं करने एवं ''पाकिस्तान से जुड़ी भावनाएं व्यक्त करने'' के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला एवं उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि वे भारत में उस देश के राजदूत हैं। जम्मू-कश्मीर के लिए पार्टी के

प्रभारी चुघ ने कहा, ''फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों पर भारत में पाकिस्तान के राजदूत का ठप्पा लगा दिया जाना चाहिए। वे जम्मू-कश्मीर में हुए उल्लेखनीय विकास और शांति को स्वीकार किए बिना पाकिस्तान की 'आईएसआई' से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है जो आईएसआई के एजेंडे को विफल करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। जब भी आईएसआई समर्थित आतंकवादी हमला करते हैं, अब्दुल्ला परिवार मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए दौड़ पड़ता है।

सेना, बीएसएफ व केंद्र की अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा

कठुआ में जम्मू-कश्मीर और पंजाब के डीजीपी के अलावा बीएसएफ और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के बीच हुई इंटरस्टेट को-ऑर्डिनेशन मीटिंग में इन बातों पर एक दूसरे से इनपुट साझा किया गया। डीजीपी गौरव यादव ने को-ऑर्डिनेशन मीटिंग के बारे में बताया कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब का एक बड़ा क्षेत्रफल पाकिस्तान से सटा हुआ है, ऐसे में इस मीटिंग में जहां दोनों प्रांतों में आतंकी गतिविधियों और उनके मॉड्यूल पर नकेल कसने के लिए इनपुट शेयर किए, वहीं दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर प्लानिंग की गई। मीटिंग में पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन और बीएसएफ के विशेष महानिदेशक पश्चिमी कमान वाई वी खुरानिया समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

आतंकवादियों के सामने न झुकें पीएम मोदी, चुनाव कराएं : उमर

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव टालने की अटकलों का जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार को आतंकवादियों के दबाव में नहीं आना चाहिए और जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से प्रतीक्षित विधानसभा चुनावों में और देरी नहीं करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मौजूदा स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी 1996 में थी। हमारे सुरक्षा बल, पुलिस और अन्य एजेंसियां आतंकवादी हमलों से निपटने और जवाब देने में सक्षम हैं, जैसा कि कठुआ में देखा गया। हालांकि स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं है। यह इतना अस्थिर नहीं है कि हम इस साल के अंत में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करा सकें।

पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करेंगे

पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि को-ऑर्डिनेशन मीटिंग में दोनों राज्यों की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर पंजाब के सरहदी इलाकों और अंतरराज्यीय सीमाओं से जुड़े जिलों में सतर्कता बढ़ाई जाएगी। मीटिंग में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तानी आतंकी पंजाब के रास्ते घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं।

पंजाब के रास्ते जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी

कठुआ में हुए आतंकी हमले के तार पंजाब से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों पठानकोट, गुरदासपुर व आसपास के बॉर्डर एरिया में संदिग्ध देखे गए थे। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पंजाब की ओर से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को आगाह भी किया गया था। इससे पहले एजेंसियां कुछ कर पातीं, आतंकियों ने आठ जुलाई को सेना के गश्ती दल पर हमला कर दिया। इस हमले में पांच जवान बलिदान हो गए। पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। छह महीने में पंजाब सीमा में घुसपैठ करते हुए 21 पाकिस्तानियों को दबोचा गया है, जो भारत में घुसने की फिराक में थे। कठुआ में सेना पर हुए आतंकी हमले के तार कहीं न कहीं पंजाब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंजाब में बीते दिनों देखे गए आतंकियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

वर्षा के मौसम खान-पान का रखें ध्यान!

आजकल वर्षा जनित रोगों की खबरें आने लगी हैं। पूरे देश में मानसून ने तेजी पकड़ ली है। मौसम में उतार चढ़ाव लगा हुआ है। कभी-कभी धूप निकल जाने से उमस बढ़ जा रही हे। उमस की वजह से बीमारी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। सरकारों द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को साफ सुथरे तरीके से भोजन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं कई बार भारत में खाए जाने भोजन की पौष्टिकता को लेकर भी रिपोर्टें आती रहती हैं। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के लगभग 40 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को कुपोषण के शिकार हैं। समय-समय पर सरकार भारतीयों के लिए खान-पान दिशा निर्देश' जारी किए जाते हैं। अभी पिछले कुछ महीने पहले हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पौष्टिकता संस्थान -जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तत्वावधान तले देश में सबसे पुरानी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में एक है, ने 'भारतीयों के लिए खान-पान दिशा निर्देश' जारी किये।

यह दस्तावेज हजारों स्वयंभू और तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा सोशल मीडिया पर पौष्टिकता, भोजन एवं खुराक को लेकर मचाये जाने वाले शोर के बीच ताजी हवा का झोंका बनकर आया है क्योंकि उक्त लोगों की भोजन और पौष्टिकता पर कही अधिकांश बातें भ्रामक और झूठी होती। आलम यह है कि एक ओर खाद्य पदार्थ उत्पादक कंपनियां और घर तक व्यंजन पहुंचाने वाले एप आधारित सेवा प्रदाता उपभोक्ता को यकीन दिलवा रहे हैं कि घर का खाना एक पाप है। वहीं फूड-ब्लॉगर हर ऐरे-गैरे रेहड़ी-ढाबे वाले के चीनी, नमक और वसा से भरे ऊलजलूल व्यंजनों को 'असली स्वाद' और 'स्वर्गिक' बताकर महिमामंडित कर रहे हैं। पौष्टिकता विशेषज्ञ और मशहूर चेहरे अंजान उपभोक्ता को खान-पान का नया चलन बताकर उलझा रहे हैं । फैक्ट्री में बने खाद्य उत्पादों पर 'स्वास्थ्यकर' व 'ताजा' का ठप्पा लगाकर बेचा जा रहा है जबकि सेहत- ताजगी से दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। निस्संदेह, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विभिन्न उम्र वर्ग और अंचल के लोगों के लिए प्रमाण-आधारित और तथ्यात्मक खुराक निर्देशावली जारी करना स्वागत योग्य है। लगभग एक सदी से एनआईएन (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन) भारत में पौष्टिकता और खाद्य संबंधी अनुसंधान कार्य में लगा है और इस विषय में ज्ञान का भंडार है। पौष्टिकता संबंधी लगभग सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि एकीकृत बाल विकास योजना, मिड-डे मील योजना और साल्ट आयोडाइजेशन के अलावा पौष्टिकता की कमी के उत्पन्न रोगों का निदान करने वाली योजनाएं एनआईएन द्वारा दिए वैज्ञानिक शोध आधारित परामर्श पर आधारित है। इस तरह के निर्देश वर्षा के समय में जरूर आते रहने चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी खानी चाहिए और कौन सी नहीं।

समय-समय पर सरकार भारतीयों के लिए खान-पान दिशा निर्देश' जारी किए जाते हैं। अभी पिछले कुछ महीने पहले हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पौष्टिकता संस्थान -जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तत्वावधान तले देश में सबसे पुरानी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में एक है, ने 'भारतीयों के लिए खान-पान दिशा निर्देश' जारी किये।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

नए बजट से मध्यम वर्ग को राहत का सवाल

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हैं। हाल ही में आयी वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मार्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के नए बजट में राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्यम वर्ग लाभान्वित होते हुए दिखाई दे सकता है। साथ ही इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना पेश की जा सकती है। नए बजट के जरिये मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है।

मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर लगातार मांग तेज हुई है। विगत वर्षों में जहां गरीब वर्ग के लिए राहतों का ऐलान किया गया, वहीं कॉर्पोरेट जगत पर भी ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मामले में सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के संबोधन में जिक्र था कि मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में रणनीति पूर्वक आगे बढ़ा जाएगा। गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024-25 के समय आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2023-24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और बीते 10 साल में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। यह फिर तेजी से बढ़ता गया। यह वर्ष 2019-20 में 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। कोरोनाकाल के कारण यह 2020-21 में कुछ घटा। लेकिन 2021-22 में 14.08 करोड़ रुपये, 2022-23 में 16.64 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 19.58 करोड़ रुपये हो गया।

ऐसी मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को राहतों से लाभान्वित

किया जा सकता है। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान नए बजट में दिखाई दे सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपये थी और वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था। मानक कटौती वह धनराशि है, जिसे वेतनभोगी करदाता अपनी कर योग्य आय में से बिना कोई सबूत दिए घटा सकता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी अपने वेतन पर ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं जहां आमदनी कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। वेतनभोगी वर्ग द्वारा नए बजट में राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है कि इस वर्ग द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी करदाता वर्ग द्वारा चुकाए गए आयकर से काफी अधिक होता है। नए बजट के तहत आयकर से संबंधित विभिन्न टैक्स छूटों में वृद्धि की जा सकती है। मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान भी शामिल है। मकानों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए धारा 80सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है ताकि टैक्पेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर प्रेरित हों। वहीं पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है।

नि:संदेह देश में कर सुधारों से आयकर संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां वर्ष 2024-25 के बजट से आयकर राहत दी जा सकती है, वहीं बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई रणनीति का ऐलान संभव है। महत्वपूर्ण यह भी कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं।

शिक्षा-रोजगार से वंचित अफगानी महिलाएं

पुष्परंजन

इस समय अफगान सिविल सेवा में जो बची-खुची महिलाएं हैं, उनकी मासिक सेलरी का अंदाजा लगा सकते हैं आप? केवल पांच हजार रुपये। भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कीजिये, तो यह केवल पांच हजार 883 रुपये बनेगा। इतने में उस महिला सिविल सेवा कर्मी को अपना घर-परिवार चलाना है। आप काम पर आइये, या घर बैठिये, मिलेगा बस पांच हजार। भारत में कामवाली बाई भी इससे कहीं ज्यादा कमा लेती है। अफगानिस्तान में औरतों का जो हाल इस्लामिक अमीरात ने किया है, उस पर इसी मंगलवार को चिंताजनक रिपोर्ट आई है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त, 2021 में 'सदाचार का प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए मंत्रालय' (एमपीवीपीवी) की स्थापना के बाद से तालिबान ने 'डर का माहौल' पैदा किया है। इस रिपोर्ट में 'मोरल पुलिस' के तौर-तरीकों पर भी सवाल किया गया है। आप वेस्टर्न हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। 'एमपीवीपीवी' ने एक रूढ़िवादी ड्रेस कोड भी लागू किया है, जो इस्लामी पोशाक को 'एक दैवीय दायित्व' के रूप में संदर्भित करते हैं। तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए पुरुष एस्कॉर्ट अनिवार्य करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा, कि वे 'उनके सम्मान और शुद्धता की रक्षा के लिए' हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) की रिपोर्ट 15 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक अमीरात में मानवाधिकार की स्थिति और मंत्रालय की कारगुजारियों पर केंद्रित है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने मंगलवार देर रात कहा कि यूएनएएमए रिपोर्ट, अफगानिस्तान को पश्चिमी नजरिये से आंकने की कोशिश कर रही है, जबकि यह एक इस्लामी समाज है। पुरुषों और महिलाओं के साथ शरिया कानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है, यहां कोई उत्पीड़न नहीं होता है।'

'यूएनएएमए' ने 15 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2024 के बीच 1033 लोगों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें 828 महिलाएं व 205 पुरुष शामिल थे। इनका जोर-जबरदस्ती का दस्तावेजीकरण किया, जहां अमीरात की मोरल पुलिस और एमपीवीपीवी ने निर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान बल प्रयोग किया। अफसोस, अफगानिस्तान का जो अकादमिक क्लास है, वो भय से अमीरात के पक्ष में भी बयान देता है। इनमें काबुल विश्वविद्यालय के व्याख्याता मोहम्मद ऐमल दोस्तयार का बयान उल्लेखनीय है। दोस्तयार कहते हैं 'दुर्भाग्य से, यूएनएएमए की हालिया रिपोर्ट वास्तविकताओं पर आधारित नहीं हैं; सदाचार मंत्रालय इन निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करता है।' सदाचार मंत्रालय के डिप्टी मोहम्मद फकीर मोहम्मदी ने कहा, कि हमने तो बल्कि 4,600 महिलाओं को विरासत प्रदान की है। इस्लामिक अमीरात महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सारे लोग अमीरात के सितम के आगे सिजदा नहीं करते। धार्मिक विद्वान खलील-उर-रहमान सईद ने बयान दिया, 'दुर्भाग्य से, हमारे देश में महिलाएं अपने बुनियादी और मानवीय अधिकारों से वंचित हैं, जिसमें विरासत, शिक्षा, काम और जीवन साथी चुनने का हक भी शामिल है।'

एक अन्य धार्मिक विद्वान हसीबुल्लाह हनफी ने महिलाओं को विरासत, शिक्षा, शादी के अधिकार से इनकार, जबरन विवाह और महिलाओं और लड़कियों को शादी में मुआवजे के रूप में देने की प्रथा के बारे में चिंता व्यक्त की है। तालिबान ने इस समय इतनी गुंजाइश दी है कि जो लड़कियां छठी कक्षा पास करने के बाद स्कूल नहीं जा सकतीं, वो घर बैठे सिलाई-कढ़ाई और कालीन बुनाई, पैकेजिंग करें। उसके लिए कार्यशालाएं खोली गई हैं। अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल रहमान हबीब कहते हैं, 'अब संबंधित मंत्रालयों ने आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं। न केवल काबुल बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों में भी, छात्राओं ने सिलाई, पेंटिंग, कालीन बुनाई और कढ़ाई जैसे व्यवसायों को सीखने की ओर रुख किया है, ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें।' लेकिन, मुल्क की महिलाएं ऐसे हालात को कुबूल करने के पक्ष में नहीं दिखतीं। इसी हफ्ते अदबी लेखिकाओं ने काबुल में एक कविता गोष्ठी आयोजित की, और इस्लामिक अमीरात से छठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों के स्कूलों को फिर से खोलने का आग्रह किया। एक प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि लड़कियों के स्कूलों को बंद करने का कोई धार्मिक औचित्य नहीं है। कार्यक्रम के आयोजकों में से एक, ओगी ने सवाल किया, 'हमारा पाप क्या यही है कि हम पुरुष नहीं हैं?'

अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल बंद हुए 292 दिन हो गए हैं। अब भी स्पष्ट नहीं है कि वे फिर से कब खुलेंगे, और भविष्य में लड़कियों के लिए क्या होगा। छात्राएं अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर तनाव में रहती हैं। उनके लगभग छह महीने के लिए विश्वविद्यालयों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने इस्लामिक अमीरात से छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का आह्वान किया। एक छात्रा खुजास्ता पूछती है, 'परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और लड़कों को परीक्षा देने और अपने विश्वविद्यालयों में जाने की अनुमति है, लेकिन लड़कियों को अनुमति नहीं है। क्यों? कारण क्या है? तालिबान ने विगत दो वर्षों में 80 फतवे जारी किए हैं, इनमें से 54 सीधे तौर पर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। वर्ष 2004 में नए संविधान में लैंगिक समानता सुनिश्चित की गई और अफगान महिलाओं के लिए संसद में 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं।

बच्चों को डायबिटीज से बचाने के लिए करें ये काम

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसके कारण शरीर के कई अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने लगता है। इसलिए बच्चों को डायबिटीज से बचाने के लिए उनकी लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी आदतों को अपनाने की सलाह देनी चाहिए। आजकल की भाग-दौड़ भरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल का प्रभाव न सिर्फ बड़ो पर, बल्कि बच्चों पर भी होने लगा है। इसकी वजह से डायबिटीज, जो एक समय में अधिक उम्र के लोगों को होती थी, आज के समय में बच्चों को भी होने लगी है। आजकल बच्चों में टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है, जिससे बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी होता है। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही हेल्दी आदतों को अपनाने की सलाह दें।

नुकसान

दरअसल, डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, जिसमें धीरे-धीरे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। इसलिए बच्चों को इस बीमारी से बचाकर रखना ही उनके लिए फायदेमंद है। डायबिटीज में बढ़ने वाले ब्लड शुगर लेवल से आंखें, किडनी और हार्ट सहित कई अन्य अंग प्रभावित होने लगते हैं। इसका कारण है कि डायबिटीज एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, जिससे छुटकारा पाना नामुमकीन है। हां, लाइफस्टाइल में बदलाव और बेहतर डाइट प्लान को फॉलो करके इससे अपने बच्चे को बचा सकते हैं।

ब्रेकफास्ट स्किप न करने दें

ब्रेकफास्ट दिन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मील होता है। एक हालिया अध्ययन में ये पाया गया है कि वे बच्चे, जो घर का बना हेल्दी नाश्ता खाते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इससे अपने बच्चे को कभी भी समझौता न करने दें। कई हेल्थ रिपोर्ट्स में पाया गया है कि सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करने से मोटापा बढ़ता है और इससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। ऐसे में अपने बच्चों को सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने की आदत डालें। घर से बाहर नाश्ता करना, नाश्ता स्किप करने के मुकाबले ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है।

फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें

आजकल के बच्चे ज्यादातर टाइम मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर गेम खेलने में अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं। ऐसे में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी न होने से बच्चों में टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। इसलिए उन्हें आउट डोर गेम्स, स्विमिंग और एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को ये उनके बढ़ते हुए शरीर को मजबूत रखने में मदद करता है। और, फलों और सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर स्वस्थ आहार के साथ, नियमित व्यायाम उन्हें कई तरह की बीमारियों और पुरानी बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

एनर्जी और शुगर वाली ड्रिंक न दें

ज्यादातर बच्चों को एनर्जी ड्रिंक या कोई भी फ्लेवर वाली शुगरी ड्रिंक बहुत पसंद आती है, लेकिन बच्चों द्वारा ऐसे ड्रिंक का सेवन टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। इसलिए अपने बच्चे को कभी भी एनर्जी या शुगर वाली ड्रिंक देने से बचें। इसकी जगह आप अपने बच्चे को नेचुरल हेल्दी ड्रिंक को दें जैसे कि नारियल पानी, ताजे फलों का जूस, लस्सी आदि।

हंसना मना है

लड़की लड़के के गले लगकर बोली...कुछ ऐसा कहो की मेरा दिल जोरो से धड़क जाए, लड़का- ऐसे ही खड़ी रह चुपचाप...पीछे तेरा बाप खड़ा है...

मेहमान- और बताओ बेटा आगे का क्या प्लान है... बच्चा- बस आपके जाते ही बिस्कुट खाउंगा... वैसे भी नमकीन और मेवा तो आपने छोड़ी नहीं है....

पति (किताब पढ़ते हुए) - एक लेखक ने लिखा है कि पतियों को भी बोलने की आजादी होनी चाहिए... पत्नी (हंसते हुए) - देखो वो भी बेचारा लिख ही पाया, बोल नहीं पाया...

टीचर- कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा। पप्पू - सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, आप चाहो तो मटर पनीर बना लेना पप्पू का जवाब सुनकर मास्टर जी ने कल के बजाए उसे आज ही मुर्गा बना दिया।

बेटा बाप से- पापा से साढू का रिश्ता क्या होता है, बाप- बेटा जब दो आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो साढू कहलाते हैं... तभी वहां मम्मी आ गई, बस फिर क्या है तब से मम्मी गुस्से से लाल हैं....और पापा डर के मारे पीले।

कहानी | आठवीं पीढ़ी की चिन्ता

एक सेठ को अपनी सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को बुलवाया गया। सेठ ने आदेश दिया- मूल्य निर्धारण अधिकतम एक सप्ताह में हो जाना चाहिए। एक सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर आया। सेठ जी ने पूछा- कुल कितनी सम्पदा है? मोटे तौर पर कहूं तो आपकी सात पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनन्द से भोग सके इतनी सम्पदा है आपकी। सेठ जी चिंता में डूब गए, तो क्या मेरी आठवी पीढ़ी भूखों मरेगी? भूख भाग चुकी थी, सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंचे एकांत में सेठ जी ने सन्त महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी! मेरी आठवी पीढ़ी के प्रयाप्त संपत्ति नहीं है। कृपया कोई उपाय बताएं आप जो भी बताएं मैं अनुष्ठान, विधि आदि करने को तैयार हूं। संत महात्मा जी बोले- इसका तो हल तो बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो, सेठ! बस्ती के अन्तिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एक दम कंगालए न कोई कमाने वाला है और न वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह यह दान स्वीकार कर ले तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ जी घर पहुंच कर सेवक के साथ एक क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढिया की झोंपड़ी पर। माताजी! मैं आपके लिए आटा लाया हूं इसे स्वीकार कीजिए। आटा तो मेरे पास है, बेटा! मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा- फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी मां ने कहा- क्या करूंगी रख कर मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले- अच्छा, कोई बात नहीं, आधा किलो तो रख लीजिए। बेटा! आज खाने के लिए जरूरी, आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी को तो सन्त महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना था। तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी मां ने कहा- बेटा! कल की चिंता मैं आज क्यों करूं, जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी, एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं आठवी पीढ़ी की चिन्ता में घुल रहा हूं। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं तृष्णा है।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद् हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी। यात्रा मनोरंजक हो सकती है। व्यापार-व्यवसाय में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। समय की अनुकूलता का लाभ लें। धन प्राप्ति सुगम होगी।

वृषभ

आय में निश्चितता रहेगी। समय शीघ्र सुधरेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। बेवजह कहासुनी हो सकती है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। धनहानि की आशंका है।

मिथुन

यात्रा सफल रहेगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप न करें। विवाद होगा। मित्रों का सहयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

कर्क

भूले-बिसरे साथियों व संबंधियों से मुलाकात होगी। कारोबार में अनुकूलता रहेगी। आत्मसम्मान बना रहेगा। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है।

सिंह

नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देगा।

कन्या

कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। बेकार बातों पर बिलकुल ध्यान न दें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा।

तुला

नए अनुबंध होंगे। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। समय की अनुकूलता रहेगी, लाभ लें। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे।

वृश्चिक

तत्काल लाभ नहीं होगा। निवेश में जल्दबाजी न करें। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। रुके कार्यों में गति आएगी। कार्यस्थल पर सुधार व परिवर्तन हो सकता है।

धनु

कारोबार में वृद्धि होगी। आसपास का वातावरण सुखद रहेगा। पार्टनरों तथा भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। विवाद को बढ़ावा न दें। विवेक का प्रयोग करें।

मकर

आय बनी रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। व्यापार-व्यवसाय की गति धीमी रहेगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें।

कुम्भ

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा।

मीन

आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। चारों तरफ से सफलता मिलेगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। उत्साह बना रहेगा। चिंता तथा तनाव कम होंगे।

इमरान हाशमी के निशाने पर आईं कंगना रणौत!

इमरान हाशमी अपने अनफिल्टर्ड स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। चाहे वह उनकी सीरियल किसर छवि हो या फिल्मी पृष्ठभूमि वह वास्तविकता को स्वीकार करने से कभी नहीं कतराते। इसी बीच इमरान हाशमी पुरस्कार समारोहों पर दिए गए अपने ताजा बयान के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। साथ ही उन्हें अभिनेत्री-राजनेत्री कंगना रणौत पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते देखा गया है।

इमरान हाशमी पुरस्कार समारोहों से बचते हैं और उन्होंने शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू में इस बारे में बात की। बातचीत के दौरान वह कंगना रणौत की टिप्पणी पर भी तंज कसते नजर आए। जानकारी हो कि कंगना रणौत ने एक बयान में कहा था कि वह अवॉर्ड शो का हिस्सा नहीं बनतीं क्योंकि उन्हें यह सब बेकार लगता है। जब इमरान से पुरस्कार शो पर उनकी राय के बारे में बात करने के लिए कहा गया, और पूछा गया कि क्या उन्हें भी अवॉर्ड शो कंगना की तरह बेकार लगते हैं, तो इस पर अभिनेता, कंगना रणौत पर तंज कसते नजर आए। अभिनेता ने कहा चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें अवॉर्ड मिलना बंद गया, शायद वह इसीलिए ऐसा कह रही हैं। इमरान हाशमी ने कहा, क्योंकि अवॉर्ड मिलना बंद हो गए उसके बाद? मुझे याद है कि एक बार मैं अवॉर्ड जीता था लेकिन जल्द ही मुझे इसके पीछे का सारा खेल समझ आ गया था। ये एक तरह की डील है तुम आओ और नाचो। इमरान ने अपनी बात में आगे जोड़ा, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा नहीं है मैं पुरस्कारों से इनकार नहीं करूंगा जिन लोगों को अपना लिविंग रूम सजाना है वो करें।

इमरान हाशमी ने अपनी बात में को जारी रखते हुए कहा, लेकिन मैं अपनी पीठ थपथपाकर यह नहीं कह सकता कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि यह झूठ है। यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको जीतना चाहिए। अगर यह बार्टर डील है तो जीतने का क्या मतलब है? इमरान हाशमी ने साफ किया कि उन्होंने इसी कारण अवॉर्ड शो का हिस्सा बनना बंद कर दिया। पुरस्कार समारोहों को लेकर कंगना रणौत की शिकायत पर चर्चा करते हुए अभिनेता ने कहा, अगर आप बाहरी व्यक्ति हैं तो किसी चीज का विरोध करना अच्छा है, लेकिन अगर आप बार-बार ऐसा कहते रहते हैं तो यह एक बाधा बन जाती है। मैं इतने कठोर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह एक बहाना है, जब आपको आगे बढ़ना चाहिए। काम के मोर्चे पर इमरान को जल्दी ही वेब सीरीज शोटाइम में देखा जाएगा।

राधिका मदान का पीछा नहीं छोड़ रहा फ्लॉप का टैग

बॉलीवुड | मसाला

साल 2014 में टीवी शो मेरी आशिकी तुम से ही के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली अभिनेत्री राधिका मदान अब बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं। उनकी अभी तक अंग्रेजी मीडियम, मर्द को दर्द नहीं होता, पटाखा, सजनी शिंदे की वायरल वीडियो और कुत्ते समेत कुल आठ फिल्में रिलीज हो चुकी है, जिनमें से कुछ सीधे ओटीटी पर भी आई थी। उनकी नई फिल्म सरफिरा कल यानी 12 जुलाई को रिलीज हो गई। इस फिल्म में उनके साथ-साथ अक्षय कुमार भी मुख्य भूमिका में दिखाई दें रहे हैं। राधिका मदान की पिछली फिल्म सजनी शिंदे की वायरल वीडियो थी। फिल्म ने 27 अक्टूबर, 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और रिलीज होते ही इसका टिकट खिड़की पर दम निकल गया था। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में सात दिनों में कुल 0.65 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया था। साल 2023 में ही आसमान भारद्वाज द्वारा निर्देशित कुत्ते का भी बुरा हाल हुआ था। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 8.47 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, कुमुद मिश्रा और कोंकणा सेन शर्मा ने भी अभिनय किया था।

अंग्रेजी मीडियम भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने में नाकाम रही थी। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 15 करोड़ रुपये कमाए थे। अंग्रेजी मीडियम में राधिका मदान, इरफान खान, करीना कपूर और दीपक डोबरियाल ने काम किया था। मर्द को दर्द नहीं होता भी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर केवल 3.5 करोड़ रुपये की ही कमाई की थी। यह राधिका की दूसरी फिल्म है, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी और इसमें भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी ने अहम रोल अदा किया था। फिल्म का निर्देशन वसन बाला ने किया था। राधिका मदान ने साल 2018 में विशाल भारद्वाज की फिल्म पटाखा के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म की कहानी तो मजेदार थी, लेकिन दर्शकों ने इसे नकार दिया था।

बॉलीवुड | मन की बात

मैडम सुषाद में अपने स्टेच्यू लगाने से आमिर ने किया मना

कुछ साल पहले आमिर खान के पास मैडम तुसाद की तरफ से खास ऑफर आया था कि वह उनका वैक्स स्टेच्यू अपने म्यूजियम में लगाना चाहते हैं। मगर एक्टर ने एक वजह के कारण इस ऑफर न कह दिया था। फिल्मों की कहानी को चुनकर पसंद करने वाले आमिर खान ग्लैमर इंडस्ट्री से होने के बावजूद भी वह खुद को इस चकाचौंध से कोसों दूर रखते हैं। यही उनको सबसे अलग बनाती है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे होंगे जिनकी ख्वाइश होगी कि उनका स्टेच्यू लंदन के मैडम तुसाद में हो। लेकिन आमिर खान अकेले ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने इस ऑफर के लिए मना कर दिया। जैसे बॉलीवुड में तीनों खान के चर्चे होते हैं, ठीक उसी तरह मैडम तुसाद भी अपने म्यूजियम में तीनों खान के वैक्स स्टेच्यू के साथ उसे और भी शानदार बनाना चाहता था। मगर एक्टर ने किसी कारण से इसके लिए मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैडम तुसाद आमिर खान के स्टेच्यू को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय की तरह उनका भी वैक्स स्टेच्यू अपने संग्रहालय में लगाना चाहता था, लेकिन आमिर खान ने उनका ऑफर ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिन चीजों में उनकी इच्छा नहीं होती वो उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आमिर खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों 'सितारे जमीन पर' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में दर्शील और आमिर के अलावा टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, तनय छेड़ा जैसे एक्टर नजर आए थे। अब आमिर खान दर्शील सफारी के साथ ही 'सितारे जमीन पर' फिल्म लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म को आर प्रसन्ना डायरेक्टर कर रहे हैं। इसमें दर्शील और आमिर के साथ जेनेलिया डिसूजा भी नजर आएंगी। ये फिल्म इस साल क्रिसमस पर थिएट्रस में दस्तक दे सकती है।

अनोखवा मंदिर... जहां प्रसाद की जगह चढ़ता है चप्पल-सैंडल

भोपाल। देशभर में देवी-देवताओं के अनेकों मंदिर हैं, जहां लोग फूल-माला और प्रसाद के साथ ही वहां की मान्यता के हिसाब से अलग तरह के प्रसाद भी चढ़ाते हैं। मंदिरों में जाने से पहले चप्पल-जूते बाहर उतार कर जाना अनिवार्य रहता है। मगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां प्रसाद के रूप में भक्त माता को चप्पल-जूते चढ़ाते हैं। आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। भोपाल के बंजारी क्षेत्र, कोलार में देवी मां का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहां माता सिद्धिदात्री विराजमान हैं। इस मंदिर को जीजाबाई माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं, स्थानीय लोग इसे पहाड़ी वाली माता मंदिर के नाम से पहचानते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये कि यहां देवी की पूजा बेटी के रूप में होती है और यहां आने वाले भक्त देवी को भेंट के रूप में नई-नई चप्पल व सैंडल चढ़ाते हैं। देवी मां के भक्त विदेशों से भी नए-नए जूते और सैंडल भेजते हैं। कोलार के बंजारी इलाके में पहाड़ी पर लगभग 125 सीढ़ी चढ़कर मां सिद्धिदात्री मंदिर पर पहुंचा जाता है। इस मंदिर की स्थापना को करीब 25 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश ने बताया कि मंदिर की स्थापना से पहले उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का विवाह कराया गया था। इस विवाह में उन्होंने पार्वती का खुद कन्यादान अपने हाथों से किया था, इसलिए ओम प्रकाश माता को बेटी मानकर पूजा करते हैं। इस मंदिर को लोग सिद्धिदात्री पहाड़ वाला मंदिर के अलावा पहाड़ा वाला मंदिर और जीजी बाई के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मां यहां बाल रूप में स्थापित हैं। बेटी की सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए बच्चों और बेटियों के उपयोग का सभी सामान मां को अर्पित किया जाता है। बेटियों की तरह उनके सारे नखरे और शौक भी पूरे किए जाते हैं। उन्हें चप्पल, चश्मा, घड़ी, छाता इत्यादि सामान चढ़ाया जाता है। यहां मां-दुर्गा की देखभाल एक बेटी की तरह होती है। ओम प्रकाश को आभास होता है कि देवी खुश नहीं हैं तो दिन में दो-तीन बार माता रानी के कपड़े बदल दिए जाते हैं। उनके मुताबिक, 25 साल में अब तक माता रानी के 15 लाख से अधिक कपड़े, चप्पल और श्रृंगार बदले जा चुके हैं। साथ ही इनका सामान भक्तों द्वारा विदेशों से भी लाया जाता है। मंदिर में जीजाबाई माता को हर रोज नई-नई पोशाक पहनाई जाती है। नवरात्रि में यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है।

अजब-गजब | नाइजीरिया के लागोस शहर में पानी के ऊपर बना है यह शहर

गैंगवार के डर से पानी पर तैरती है ये झोपड़पट्टी, यहां नाले में चलती है नाव

आपने मुंबई के धारावी को सामने से या फिर फिल्मों में तो जरूर देखा होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों में से एक है। पर अफ्रीका के एक देश में ऐसी झोपड़पट्टी है जिसका हाल देखकर आपको धारावी या भारत के छोटे शहरों में बनी झुग्गी झोपड़ी भी आलीशान लगेगी। अफ्रीका की ये झोपड़पट्टी पानी पर तैरती है। चारों ओर नाले का गंदा पानी है जिसपर नाव चलाकर ही लोग आते-जाते हैं। यहां का सबसे बड़ा खतरा है गैंगवॉर। जिसकी वजह से लोगों की जान भी जाती है और उसके डर में यहां के लोग जीते हैं।

डेनियल पिंटो एक ट्रैवलर और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर हैं, जो हाल ही में अफ्रीका के नाइजीरिया गए और वहां के एक शहर में बनी तैरने वाली झोपड़पट्टी को दिखाया। इस जगह का नाम है मकोको, जो नाइजीरिया के लागोस शहर में पानी के ऊपर बना एक बड़ा स्लम है। हैरानी की बात ये है कि यहां पर लोग नाले के गंदे पानी के बीच लकड़ियों के घर में रहते हैं। पानी पर नाव चलती है, इसी वजह से इसे नाइजीरिया का वेनिस भी कहा जाता है। अब इतने खूबसूरत शहर की तुलना इस जगह से करना बेवकूफी है, मगर यहां के लोग इसे वेनिस ही मानते हैं।

डेनियल ने इस जगह का एक वीडियो पोस्ट किया जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो नाव में यात्रा कर रहे हैं। वीडियो में बताते हैं कि ये जगह खतरनाक भी है क्योंकि इस जगह पर गैंग्स का काफी वर्चस्व है और आए दिन गैंग वॉर होती रहती है। पानी के चारों ओर काफी कूड़ा-कचड़ा देखने को मिल रहा है। डेनियल ने बताया कि ये जगह 19वीं सदी की शुरुआत में बसी थी, जिसे मछुआरों ने बसाया था। उन्होंने यहां पर बसना इस वजह से चुना क्योंकि ये जगह मछली पकड़ने के लिए काफी उपयुक्त थी। उन्होंने बताया कि विदेशियों को यहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनसे जबरन पैसे वसूल लिए जाते हैं। वो लकड़ी के तख्तों पर भी चलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ रुपयों में लोग यहां की सैर कर सकते हैं।

कई लोगों ने कहा कि नाइजीरिया में काफी विकसित जगहें भी हैं, उन्हें उन जगहों पर जाकर नाइजीरिया की सुंदरता को भी दिखाना चाहिए। एक ने कहा कि विदेशी वहां जाकर उस जगह को झोपड़पट्टी क्यों बोलते हैं, वो उनके जीने का तरीका है।

एलजी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर उपराज्यपाल की भूमिका की निंदा

» अदालत ने पूछा- क्या उपराज्यपाल खुद को अदालत समझते हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना खुद को अदालत समझते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में एलजी की भूमिका की निंदा की। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले ही दिन बता देना चाहिए था कि एलजी ने पेड़ काटने के आदेश दिए थे।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि याचिका यहां लंबित होने के बावजूद पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में एलजी ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पीठ ने एलजी की भूमिका को छिपाने के प्रयास की भी निंदा की। जस्टिस ओका ने कहा, पहली तारीख को हमें बताया जाना चाहिए था कि एलजी ने निर्देश दिए थे। एलजी की भूमिका हमें तब ही समझ में आ गई थी जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी खुद हमारे सामने आए थे। पीठ ने कहा, हलफनामे से पता चलता है कि डीडीए ने एलजी से अनुमति मांगी थी। एलजी ने भी पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने मान लिया कि दिल्ली सरकार के पास 'ट्री ऑफिसर' की शक्ति है। पीठ ने सवाल किया कि क्या डीडीए के अधिकारियों ने एलजी को बताया था कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी है।

दिल्ली सरकार भी 422 पेड़ काटने का दोष माने

पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार को भी 422 पेड़ों को काटने की अवैध अनुमति देने का दोष स्वीकार करना चाहिए। सरकार को इस अदालत को बताना चाहिए कि वह पेड़ों की इस अवैध कटाई की भरपाई कैसे करेगी। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मंजूरी दे दी थी, जबकि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि पहले न्यायालय से अनुमति की जरूरत है।

केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा

शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से जमानत देने का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत मिली गिरफ्तारी की शक्ति जांच के उद्देश्य के लिए नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब संबंधित अधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिखित में कारण दर्ज करने के बाद यह राय बनाने में सक्षम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है। यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के विश्वास योग्य कारण बताना भी कानूनी रूप से अनिवार्य है। पीठ ने कहा, गिरफ्तारी के लिए इंतजार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

विझिंजम पोर्ट को लेकर कांग्रेस-सीपीआईएम में रार

» दोनों में छिड़ा क्रेडिट वॉर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोच्चि। विझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट के उद्घाटन को लेकर केरल में मार्क्सवादी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक श्रेय की लड़ाई छिड़ गई। कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना शुरू करने का श्रेय लिया, सीपीआई (एम) ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद कायम रही। कांग्रेस ने इस परियोजना की परिकल्पना का श्रेय अपने अनुभवी नेता दिवंगत ओमन चांडी को दिया।

विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने बताया कि पिनाराई विजयन, जो 2015-16 में बंदरगाह का निर्माण शुरू होने पर सीपीआई (एम) सचिव थे, ने शुरू में इसे 6,000 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट उद्यम के रूप में खारिज कर दिया था। क्या आज भी रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है? सतीसन ने कहा, ओमन चांडी ने तब प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस परियोजना को पूरा करेंगे। सीपीएम ने लोगों और विपक्ष के महत्वपूर्ण विरोध के बीच परियोजना के प्रति मुख्यमंत्री विजयन की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए कांग्रेस के दावों का खंडन किया। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने और परियोजना को रोकने का आह्वान करने का भी आरोप लगाया। यह पहली बार नहीं है जब परियोजना का श्रेय लेने के लिए दोनों पक्षों के बीच इस तरह की लड़ाई छिड़ी हो। अक्टूबर 2023 में, जब पहला जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, तो कांग्रेस ने बंदरगाह की योजना का श्रेय लिया।

जल्द बहाल हो पुरानी पेंशन

» चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राम राज दूबे ने की प्रेस वार्ता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम राज दूबे ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ पिछले 6 वर्षों से इस मुद्दे पर लगातार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देता रहा है और पत्रकारों के माध्यम से भी अवगत कराता रहा है।

प्रेस वार्ता में संघ के अध्यक्ष राम राज दूबे ने कहा कि अगर अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद सांसद और विधायक को पेंशन मिल सकती है, तो राज्य कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में खून पसीना बहाकर जी तोड़ मेहनत करता है, उसको पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। आखिर में अध्यक्ष कहते हैं यह समस्या वर्ष 2005 के बाद सरकारी नौकरी में आए समस्त कर्मचारियों के साथ हो रही है, जिसका मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और संघ उठाता रहेगा। अगर जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो सभी कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

अगर हम ऐसी ही गलती करते रहे तो जनता सत्ता से दूर कर देगी : गडकरी

» भाजपा नेताओं को चेतावनी- हम अलग सोच वाली पार्टी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने नेताओं और अपनी पार्टी की तारीफ की तो वहीं उसे आगाह भी किया। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी अलग सोच वाली पार्टी है और यही कारण है कि वह लगातार जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने भगवा दल को अतीत में कांग्रेस की गलतियों को दोहराने से बचने की भी बात कही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अतीत में कई गलतियां की जिसकी वजह से उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा, अगर यही गलती हम भी करते हैं तो फिर उनके सत्ता से जाने और हमारे आने को कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। करीब 40 मिनट के भाषण में नितिन गडकरी ने पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी को अलग सोच वाली पार्टी बताया था। आडवाणी जी कहते थे कि हम अलग सोच वाले हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम अन्य राजनीतिक दलों से कितने अलग हैं, हमें ये जानना चाहिए कि राजनीति के जरिए सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सकता है।

व्यक्ति की पहचान उसके मूल्यों से होती है जाति से नहीं

नितिन गडकरी ने अपने भाषण के दौरान जाति आधारित राजनीति के चलन की आलोचना करते हुए कहा, जो करेगा जात की बात, उसे पड़ेगी कसकर लात। वो बोले, मैंने व्यक्तिगत तौर पर जातिगत चलन पर न चलने का निर्णय लिया है और जाति आधारित राजनीति में नहीं पड़ूंगा। गडकरी ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके मूल्यों से होती है जाति से नहीं।

तमिलनाडु में नेता भी सुरक्षित नहीं : मुरुगन

» दलितों पर अत्याचारों के विरोध में उतरी बीजेपी

» डीएमके ने किया पलटवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में द्रमुक और भाजपा के बीच भिड़ंत जारी। केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने आरोप लगाया है कि दलितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं और द्रमुक सरकार के शासन में राज्य में नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। कहा, मई 2021 में द्रमुक के सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ अत्याचारों में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार के 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने 2022 से दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं और भाजपा नेताओं पर हमले और हत्या की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की 'पूर्ण विफलता' को जिम्मेदार ठहराया। मुरुगन ने कहा,'हाल ही में दलित नेता और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई।' अनुसूचित जाति के नेताओं और लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। द्रमुक सरकार में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 में तमिलनाडु भाजपा के कोषाध्यक्ष शंकर की हत्या कर दी गई, उसके बाद अगस्त 2023 में एक छात्र की क्रूर हत्या की गई। उन्होंने कहा कि एक अन्य घटना में एक स्थानीय द्रमुक पदाधिकारी ने भाजपा तमिलनाडु युवा शाखा के नेता जगन पांडियन पर घातक हमला किया। मुरुगन ने कहा कि द्रमुक का दावा है कि वह सामाजिक न्याय की प्रणेता है, लेकिन सत्तारुढ़ पार्टी राज्य में सामाजिक न्याय के विचार का पालन नहीं कर रही है।

भाजपा बार-बार हार के बाद भी नहीं ले रही सबक : स्टालिन

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि केंद्र में भाजपा ने तमिलनाडु में बार-बार चुनावी तौर पर शिकस्त खाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा है। उन्होंने साथ ही भाजपा पर राज्य में प्रमुख परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर नहीं करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि जनता के लिए समर्पित कार्य विपक्षी दलों के लिए ईर्ष्या पैदा कर रहे हैं और इसीलिए वे दुष्प्रचार के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए है, चाहे उन्होंने द्रमुक को वोट दिया हो या नहीं, दूसरों में ऐसी उदारता नहीं देखी जा सकती।

संविधान हत्या दिवस को लेकर एनडीए सरकार पर विपक्ष का तीखा प्रहार

कांग्रेस का तंज- देश के लोग अब आठ नवंबर को मनाएंगे आजीविका हत्या दिवस, जल्द ही जारी होगी नोटिफिकेशन

जयराम रमेश बोले- हेडलाइन मैनेज करने के लिए लिया फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा 25 जून 1975 (आपात) को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के सरकार के कदम पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति की है। कांग्रेस के साथ ही आप व राजद ने भी मोदी सरकार के नोटीफिकेशन को गलत बताया है। सरकार के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए, विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अब से, हर साल 8 नवंबर को, जिस दिन 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी, भारत के लोग आजीविका हत्या दिवस मनाएंगे और एक गजट अधिसूचना भी जारी की जाएगी।

कांग्रेस महासचिव (प्रभारी, संचार), जयराम रमेश ने कहा ने कहा कि आज नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को हेडलाइन मैनेज करने की तत्काल आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सीधा सा जवाब है, अभी जारी सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि खाद्य मुद्रास्फीति मई 2024 में 8.69प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 9.55प्रतिशत हो गई है।

10 सालों में मोदी सरकार ने हर दिन संविधान की हत्या की : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया कि पिछले 10 सालों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस मनाया है। बीजेपी-आरएसएस संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना चाहती है ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हमला किया जा सके! इसीलिए बीजेपी-आरएसएस संविधान के पवित्र शब्द में हत्या शब्द जोड़कर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रही है।

भारत के लोग जुमलों में नहीं फंसेंगे : झा

राजद नेता मनोज झा ने कहा, देखो कौन बोल रहे हैं ये बात?...उन्होंने संविधान को नष्ट कर दिया है...उन्हें अपने सामने एक दर्पण रखना चाहिए। कुछ साल पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की गई थी, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भारत के लोग अब आपके जुमलों में नहीं फंसेंगे।

आपातकाल के बाद भी कांग्रेस जीती : डीके

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और पी. वी. नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है। इस देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास बहाल किया।

अपनी तानाशाही खत्म करे भाजपा : गोपाल

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, संविधान की आत्मा लोकतंत्र, विपक्ष, न्यायपालिका और पत्रकारिता है, लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा करना था,भाजपा को अपनी तानाशाही खत्म करनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए।

चुनाव के परिणाम से बहुत परेशान है बीजेपी : अजय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता ले, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीजों को रोक सकते है।

बालासाहब ठाकरे ने किया था आपातकाल का समर्थन

शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा बालासाहब ठाकरे ने खुलकर साल 1975 में लगाए गए आपातकाल का समर्थन किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया था और जब वे मुंबई आईं थी तो उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने आपातकाल का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि देश में अराजकता को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसमें क्या गलत था? संजय राउत ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के बीते 10 वर्षों में जो हुआ, उसे भी याद रखा जाएगा। वे भी संविधान के रक्षक नहीं हैं।

इमरजेंसी के बचाव में उतरे शिवसेना नेता संजय राउत

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस सरकार द्वारा साल 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के फैसले का बचाव किया है। इस पर संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला और दावा किया कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लागू कर देते। संजय राउत ने कहा आपातकाल लागू हुए 50 साल बीत चुके हैं और लोग भी आपातकाल को भूल चुके हैं।

फोटो :4 पीएम

समारोह डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करते भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ।

कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार : ममता

» उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद बंगाल सीएम का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार की स्थिरता के बारे में संदेह व्यक्त किया है और सुझाव दिया है कि वह सत्ता में नहीं रह सकती है। उनकी यह टिप्पणी मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद आई।

ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर मुलाकात की, जो लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों नेता विपक्ष के इंडिया गुट का हिस्सा हैं और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि बैठक में भविष्य की चुनावी लड़ाइयों से पहले अपने सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया ब्लॉक के निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया गया। बनर्जी ने एनडीए सरकार की स्थिरता के बारे में चिंता जताई और सत्ता बनाए रखने में संभावित चुनौतियों का संकेत दिया।

उनकी टिप्पणियाँ उनके व्यापक राजनीतिक आख्यान के हिस्से के रूप में सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिरता पर सवाल उठाने की विपक्ष की रणनीति को उजागर करती हैं। उनकी बैठक और बनर्जी की टिप्पणियों ने विपक्षी नेताओं द्वारा एकजुट मोर्चा पेश करने और आगामी चुनावों में एनडीए सरकार को चुनौती देने के ठोस प्रयास का संकेत दिया।

मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी

ममता बनर्जी ने आपातकाल को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी है। ममता ने कहा कि नए क्रिमिनल लॉ को कोई नहीं जानता।

गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर आठ विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राजभवन की देरी से उन लोगों के कल्याण पर असर पड़ रहा है जिनके लिए बिल सदन में पारित किए गए थे। वकील आस्था शर्मा ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका दायर की थी, और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शीघ्र सुनवाई पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।

बाढ़ हुई विकराल, जीवन-यापन मुहाल

यूपी से असम तक पानी ही पानी, सैकड़ों की मौत, हजारों लोगों का पलायन, हाईवे पर शरण ले रहे लोग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहरों में अब बाढ़ का असर विकराल रूप लेता जा रहा है। वहीं मानसून की बारिश के साथ ही बाढ़ ने देश के पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक कहर बरपाया है। हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन से जीवन-यापन दूभर हो गया है। मुंबई समेत कई समुद्री शहरों में आरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

उधर यूपी के बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और पीलीभीत के करीब 222 गांव की बड़ी आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। पूर्वांचल के बलिया में भी बाढ़ की स्थिति के चलते कुछ घर बहने की खबर है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ का पानी दूसरे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रहने के कारण कार-बाइक व अन्य छोटे वाहनों का संचालन बंद रखा गया। बाढ़ के कारण रोडवेज बसें भी नहीं चलीं।

मुरादाबाद- लखनऊ के बीच नए 22 कॉशन तय करके ट्रेनों को भी धीमी गति से गुजारा जा रहा है। आलम यह है कि लोगो को ऊंचाई वाले जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।